GIRIDHAR GOMANGO) : (a) to (c) No programme named, 'New Package Programme' is being implemented, or funded by the Planning Commission in the State of Gujarat. Therefore, the question of identification of development blocks or activities under the programme or allocation of funds under it does not arise.

निर्माणाधीन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

2476. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 6-12-93 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं. 385 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है कि जिनकी लागत में वृद्धि हो गई है तथा उनके संबद्ध मंत्रालयों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने में हो रहे असाधारण विलम्ब को देखते हुए सरकार एक पृथक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 385 दिनांक 6-12-93 के संदर्भ में, 109 परियोजनाओं में मूल लागत के मुकाबले 50% से अधिक लागत वृद्धि हुई है। परियोजनाओं की संख्या और संबंधित क्रमशः मंत्रालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

@2476-ए. **श्री सोमपाल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद बैठकें किस-किस तारीख को हुई और उनमें क्या निर्णय लिये गये ; और

(ख) उक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ने अब तक क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

विवरण

(क) और (ख) इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय विकास परिषद की दो बैठकें, एक 5 अप्रैल, 1993 को तथा दूसरी 18 सितम्बर, 1993 को आयोजित की गई। अप्रैल, 1993 को आयोजित बैठक में एनडीसी की मितव्ययता संबंधी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।

समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों का आमतौर पर समर्थन करते हुए परिषद ने योजना आयोग को इनकी सिफारिशों पर व्यापक विचार विमर्श करने का निदेश दिया। विद्युत संबंधी एक एनडीसी समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के अनुसार निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की गई :--

(i) योजना आयोग ने अप्रैल—जून 1993 के दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों तथा नैशनल काउंसिल (जे सी एम) स्टाफ साइड केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ सहित व्यापार संघों के साथ विचार-विमर्श किया। इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राष्ट्रीय विकास परिषद को 18 सितम्बर, 1993 को

@ पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3025, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 से स्थानान्तरित।

विवरण

50 प्रतिशत एवं उससे अधिक लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं और संबंधित क्षेत्र/मंत्रालयों/विभागों का ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्र/विभाग/मंत्रालय	परियोजनाओं की कुल संख्या	लागत वृद्धि वाली परियोजनाएं			
			संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	परमाणु ऊर्जा	4	3	1824.8	5717.0	213.3
2.	नागर विमानन	11	2	1168.8	2523.7	115.9
3.	कोयला	69	20	3378.7	7471.0	121.1
4.	उर्वरक	3	1	88.0	782.5	788.9
5.	सूचना और प्रसारण	8	3	63.7	166.3	161.1
6.	खानें	1	0	0.0	0.0	0.0
7.	इस्पात	9	4	4273.7	8611.0	101.5
8.	रसायन एवं पैट्रोरसायन	9	1	34.9	75.0	115.2
9.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	38	12	7033.9	14297.3	103.3
10.	विद्युत	44	21	10647.9	27398.3	157.3
11.	भारी उद्योग	8	5	594.0	1128.8	90.0
12.	रेलवे	93	27	1848.7	6364.6	244.3
13.	भूतल परिवहन	31	9	526.5	1033.9	96.4
14.	दूर-संचार	22	1	18.1	28.6	58.3
15.	शहरी विकास	6	0	0.0	0.0	0.0
	योग :	356	109	31501.6	75598.0	140.0

आयोजित इसकी बैठक में प्रस्तुत की गई । राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस पर विचार किया ।

(ii) टैरिफ दरें संशोधित करके, दक्षता सुधार तथा उत्पादन से वितरण को अलग करने पर विचार करने के द्वारा राज्य बिजली बोर्डों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के उपायों की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी एक एन डी सी समिति का गठन किया गया ।

18 सितम्बर, 1993 को आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में रोजगार जनसंख्या साक्षरता तथा सूक्ष्म स्तरीय आयोजना तथा प्राथमिक स्तर पर लोगों की सहभागिता संबंधी चार एन डी सी उप समितियों की रिपोर्टों तथा "सभी के लिए शिक्षा" संबंधी एक आलेख पर विचार विमर्श किया गया । राष्ट्रीय विकास परिषद ने उपर्युक्त उप समितियों की सिफारिशों का समर्थन किया तथा नौडल मंत्रालयों अर्थात् साक्षरता और सभी के लिए शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वृहद स्तरीय आयोजना तथा रोजगार सृजन के लिए योजना आयोग को आगे की कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया है।

12:00 Noon.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT (1992-93) OF THE RUBBER BOARD, KOTTAYAM AND RELATED PAPERS.

1. THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Annual Report of the Rubber Board, Kottayam, for the year 1992-93.

(ii) Review by Government on the working of the above Board.

(Placed in Library, *See* No. LT-4972/93)

REPORT AND ACCOUNTS (1992-93) OF THE INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, CALCUTTA AND ALLIED PAPERS.

2. THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : I lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers :—

(i) Sixty-first Annual Report and Accounts of the Indian Statistical Institute, Calcutta, for the year 1992-93, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(ii) Review by Government on the working of the above Institute.

(Placed in Library. *See* No. LT-4738/93).

I. REPORT AND ACCOUNTS (1992-93) OF THE CASHEW EXPORT PROMOTION COUNCIL OF INDIA, COCHIN AND RELATED PAPERS.

II. REPORT AND ACCOUNTS, (1992-93) OF THE NATIONAL CO-OPERATIVE CONSUMERS FEDERATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI AND RELATED PAPERS.

III. NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF COMMERCE.

IV. NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION.

V. NOTIFICATIONS OF THE MINISTRY OF COMMERCE.

3. THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : I lay on the Table—

A copy each (in English and Hindi) of the following papers :—